पहली बार सिंहस्थ के मद्देनजर विकास प्राधिकरण बनाएगा 13 सड़कें

- टू-लेन, फोरलेन तो 3 सिक्स -लेन का होगा निर्माण
- टेंडर प्रक्रिया पूरी, अब निर्माण होगा शुरू
- 24 मीटर से 18 मीटर करने पर फंसा पेज

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन विकास प्राधिकरण शहर में परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सड़क निर्माण का काम शुरू करने जा रहा है. प्राधिकरण कुल 13 महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण करेगा. इनमें कुछ मार्ग टू-लेन, कई फोर-लेन और प्रमुख मार्ग 6-लेन बनाए जाएंगे. सभी सड़क परियोजनाओं के टेंडर पूरे हो चुके हैं और अब निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से आरंभ होगा.

यह कार्य योजना विशेष रूप से इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 2028 में करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक उज्जैन पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले में सिंहस्थ तैयारियों की गति तेज हो गई है और यह सड़कें ट्रैफिक दबाव कम करने के साथ शहर की कनेक्टिविटी बेहद सुगम बनाएंगी.

सिक्स लेन सड़कों पर विवाद

इधर पिपली नाका से गढ़कालिका, भैरवगढ़ सिक्स लेन, कार्तिक मेला ग्राउंड, दत्त अखाड़ा, भूखी माता सिक्स लेन और गढ़कालिका मंदिर से श्मशान घाट तक सिक्स लेन सड़क को लेकर विरोध भी तेज हो गया है. क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इन तीनों मार्ग को सिक्स लेन से फोर लेन किए जाने की मांग उठाई है. अभी इस पर अंतिम निर्णय शेष है. उधर, विकास प्राधिकरण भी असमंजस में है कि सड़क चार लेन बनेगी या छह लेन, जबकि इस मार्ग को सिक्स लेन बनाने की पूर्व में भोपाल से सहमति मिल चुकी है.

प्रभावित मकान-दुकान वालों को नोटिस-सड़क चौड़ीकरण के तहत कई मार्गों पर मकान-दुकान प्रभावित होंगे. प्राधिकरण ने प्रभावित रहवासियों, व्यापारियों और संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया है. प्रशासन का दावा है कि मुआवजा और पुनर्वास नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सिक्स लाइन में टूटेंगे लगभग 300 मकान दुकान- क्षेत्रीय रहवासियों से लेकर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा भी इसलिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से गुहार लगा रहे हैं कि जो सिक्स लेन का निर्माण विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है. वह यदि फोरलेन में तब्दील नहीं किया गया तो 300 से अधिक मकान दुकान प्रभावित होंगे. रहवासियों ने ब-मुश्किल अपने आशियाने बनाए हैं और उन्हें तोड़ा जाएगा तो काफी नुकसान होगा ऐसे में मांग की जा रही है कि सिक्स लेन को फोर लाइन कर दिया जाए.

जानिए कौन-कौन सी 13 सड़कें बनेंगी

जुना सोमवारीया से पिपली नाका, अंकपात चौराहा 1.78 किमी/ 4 लेन/ लागत 23.99 करोड़, कार्तिक मेला ग्राउंड से नईखेड़ी मार्ग सिंहस्थ बायपास तक 2.67 किमी/ 4 लेन/ लागत 36.59 करोड़, महाराजा वाड़ा से हरसिद्धि मंदिर, शिप्रा तट 0.64 किमी/ 4 लेन/ लागत 24.46 करोड़, कर्कराज पार्किंग से भूखी माता मार्गएमआर -22-2.09 किमी/ 4 लेन/ लागत 11.94 करोड़, भरथरी गुफा से ऋण मुक्तेश्वर तक- 0.8 किमी/ 2 लेन/ लागत 7.79 करोड़, गढ़कालिका मंदिर से वीर सावरकर मार्ग, पीरमत्स्येंद्रनाथ समाधि- 0.4 किमी/ 2 लेन/ लागत 3.04 करोड़, प्रशांति धाम से शनि मंदिर एम आर-27- 1.2 किमी/ 2 लेन/ लागत 9.04 करोड़, शिप्रा नदी पश्चिम प्रस्तावित एमआर -22- 11.12 किमी/ 6 लेन/ लागत 193.33 करोड़, शनि मंदिर से जीवनखेड़ी मार्ग एमआर- 2.35 किमी/ 6 लेन/ लागत 58.27 करोड़, पीपलियाना से गढ़कालिका- श्मशान घाट- 1.91 किमी/ 6 लेन/ लागत 83.59 करोड़, भैरवगढ़ जेल चौराहा से पिपली नाका- 2.00 किमी/ 6 लेन/ लागत 89.17 करोड़, कालीदास मेला ग्राउंड क्षेत्र व उजड़खेड़ा हनुमान कनेक्टिविटी- 1.9 किमी/ 6 लेन + 2.6 किमी/ 4 लेन/ लागत 64.89 करोड़. खाक चौक- वीर सावरकर- गढ़कालिका- भर्तृहरि गुफा- 2.42 किमी/ 4 लेन/ लागत 24.97 करोड़ प्रमुख है.

कर्ज को कर्ज नहीं निवेश कहेंगे

- उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकार वार्ता में कहा
- समय पर कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने का दावा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 दिसंबर. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर नई थ्यौरी दी है. उन्होंने कहा कि कर्ज को कर्ज नहीं निवेश कहेंगे. हम भारत सरकार के नियम के तहत ही कर्ज ले रहे हैं, उस कर्ज को समय पर चुका रहे हैं.

कर्ज लेकर हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं. कर्ज की राशि को केवल पूंजीगत मद में ही खर्च कर रहे हैं. यह दावा उन्होंने गुरुवार को वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान किया. इस दौरान अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने साफ किया कि कर्ज केवल पूंजीगत कार्यों के लिये ही लिया जा रहा है. इस राशि को राजस्व मद में खर्च नहीं किया जा रहा है, केवल कोविड काल के दो वर्षों में ही कर्ज की राशि को राजस्व मद में उपयोग किया था, उसके बाद नहीं किया. उन्होंने कहा कि जीएसडीपी का 3 फीसदी तक हम कर्ज ले सकते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में लिमिट 45 हजार करोड़ रुपये थी, वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसडीपी के आकार 16.94 करोड़ होने पर कर्ज की लिमिट लगभग 51 हजार करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य और देश बिना कर्ज की राशि के विकास नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि हम कर्ज की मूल राशि के साथ ही ब्याज के 28 से 29 हजार करोड़ रुपये भी लौटा रहे हैं.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली के लिये जो लक्ष्य तय किया है, उसमें हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य हासिल कर लेंगे या फिर उससे भी अधिक तक पहुंच जाएंगे.

इसके लिये हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. लाड़ली बहनों को प्रतिमाह 5 हजार रुपये तक दिये जाने को लेकर सीएम द्वारा दिये गये बयान के संबंध में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि सीएम साहब ने जो भी कहा है उसे पूरा करेंगे. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55 हजार 634 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर तक कुल 34 हजार 829 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर तक डाटा एनालिटिक्स आधारित चिन्हित प्रकरणों में प्रवर्तन कार्यवाहियों से रु. 967 करोड़ एवं ऑडिट की कार्यवाही से. 404 करोड़ रु का राजस्व प्राप्त हुआ है। बुरहानपुर, राजगढ़, खरगोन, झाबुआ, कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों में नवीन कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

मदिरा निर्यात के लिये एकीकृत पॉलिसी बनेगी

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि राजस्व में वृद्धि के लिये राज्य तथा देश के बाहर मदिरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एकीकृत पॉलिसी बनाई जाएगी. मदिरा उपभोग/विक्रय के एक दिवस का लायसेंस मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से जारी किया जाएगा. प्रदेश के समस्त शासकीय विभाग, निगम, मंडल द्वारा दिए जा रहे वर्क आर्डर तथा भुगतान की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके इसके लिये डाटा रिपोजटरी बनाया जाएगा.

दीन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा : राज्यपाल मंगुभाई

भोपाल, 18 दिसंबर. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि दीन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा है. पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है.

राज्यपाल ने गुरुवार को भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बी.एम.एच.आर.सी.) में आयोजित चौथे इंटरनेशनल स्कूल ऑन रेडिएशन रिसर्च के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए चिकित्सक भगवान का अवतार होते हैं. उपचार के दौरान चिकित्सक का मरीजों के साथ व्यवहार बहुत मायने रखता है. चिकित्सक की आत्मीयता, सरलता व सहजता मरीज के मनोविज्ञान और उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इस अवसर पर अस्पताल की प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव भी मौजूद थीं.

राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की रिपोर्ट 15 जनवरी तक पेश करें

- उच्च न्यायालय ने केंद्र शासन को दिए निर्देश

इंदौर. इंदौर से मुम्बई जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 पर दुर्घटनाओं के मद्देनजर बाकानेर घाट के साईड से वैकल्पिक मार्ग 106 करोड़ रूपये की लागत से 8.8 कि.मी. का बनाया गया था लेकिन निर्माण के मात्र 6 माह बाद ही यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई. इस मामले को लेकर आज उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र शासन की ओर से समय मांगा गया. इसके पश्चात न्यायालय ने 15 जनवरी 2026 तक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.

उक्त निर्देश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला एवं न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी द्वारा सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बी.एल. जैन द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका की सुनवाई पश्चात जारी किए गए है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक तुगनावत द्वारा न्यायालय को बताया गया कि 13 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगणों को निर्देशित किया गया था कि, उक्त मार्ग की बदहाली को दूर करते हुए 15 दिसम्बर 2025 तक न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करें लेकिन केन्द्र शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस प्रकरण में सुनवाई हेतु मुम्बई से सीनियर एडवोकेट उपस्थित होने वाले थे लेकिन वे आज यहां उपस्थित नहीं हो सके इसलिये सुनवाई हेतु समय दिया जाए. इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि हमारे द्वारा इस मामले में सड़क को सुधार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था लेकिन आज आपके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई एंव सीनियर एडवोकेट की उपस्थिति हेतु समय चाहा जा रहा है.

आम जनता भुगत रही खामियाजा

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि एक माह पूर्व न्यायालय द्वारा सडक सुधार के संबंध में रिपोर्ट चाही गई थी एवं केन्द्र शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने सड़क सुधार करवाने का आश्वासन भी दिया गया था लेकिन अभी तक न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है परिणाम स्वरूप इसका खामियाजा आम जनता को प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा है. इस पर न्यायालय ने कहा कि प्रतिदिन वाहन चालको को आवागमन में हो रही असुविधा को देखते हुए न्यायालय के समक्ष 15 जनवरी के पूर्व वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

बोत्सवाना के दल ने कूनो पार्क में तैयारियों का लिया जायजा

ग्वालियर, 18 दिसंबर. प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों की तीसरी खेप बोत्सवाना से लाई जानी है.

इसी के चलते बोत्सवाना का 3 सदस्यीय दल श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचा और यहां भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को लेकर की जा रही तैयारियां देखीं और बनाए गए क्वारंटीन बाड़ों का जायजा लिया. विदेशी टीम ने इस दौरान सभी तैयारियां और इंतजाम बेहतर होने पर सराहना की.

एनएच-52 अब जल्द होगा सिक्स लेन

190 सड़क हादसे हो चुके हैं

बड़वानी, 18 दिसम्बर. मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित बिजासन घाट में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के पत्र पर संज्ञान लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कर इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए एक पत्र सौंपा था।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह प्रभावी कदम

डॉ सोलंकी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को बिजासन घाट क्षेत्र में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इंदौर से बिजासन घाट तक के राष्ट्रीय राजमार्ग-52 को तथा आगे महाराष्ट्र सीमा तक सड़क को सिक्स लेन में परिवर्तित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री यादव से बिहार की खेल मंत्री की सौजन्य भेंट

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह तथा बिहार के खेल महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में सौजन्य भेंट की.

मोबाइल एप बताएगा किस रोड पर टोल ज्यादा

लोनिवि मंत्री राकेश सिंह ने दी जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 दिसंबर. प्रदेश में शीघ्र ही लोकपथ मोबाइल एप-2 शुरू होगा. इस मोबाइल एप के माध्यम से पहले ही हमें ये पता चल जाएगा कि जिस रोड पर हम चल रहे हैं, वहां हमारे गंतव्य तक पहुंचने में कितने टोल मिलेंगे, उन टोल पर हमें कितना रुपया देना होगा? क्या कोई वैकल्पिक रास्ता भी है, जहां कि कम टोल देना पड़ेगा.

इतना ही नहीं हम जिस रोड पर चल रहे हैं उसमें कितने ब्लैक स्पॉट है. जिस रोड से हम गुजर रहे हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में कितने पर्यटन स्थल हैं, उनकी दूरी क्या है.

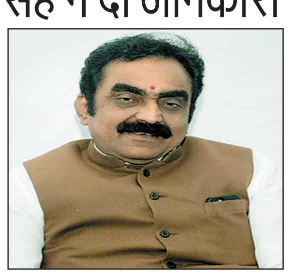

यह जानकारी गुरुवार को दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी. उन्होंने बताया नया एप भी जल्द ही आएगा. पुराने एप में भी खराब सड़कों की फोटो अपलोड करने के बाद महज चार दिन के भीतर मरम्मत सुनिश्चित किया गया है. मंत्री ने बताया कि विभाग ने भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से एरियल दूरी की तुलना कर नए एलाइनमेंट की प्लानिंग और डीपीआर तैयार करने की योजना तैयार की है. इससे पूरी एक्यूरेसी के साथ डीपीआर तैयार होगा. परियोजना के अलाइन्मन्ट से गुजरने वाले अन्य यूटिलिटी, वन भूमि आदि का सही तरीके से चिन्हांकन किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण में नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, अब किस सड़क परियोजना की वास्तविक लागत कितनी होगी, इसका सही आकलन किया जा सकेगा, वहीं परियोजना को कितनी अवधि में पूरा किया जाएगा, ये पहले से ही तय होगा. अभी केवल अनुमान के आधार पर समय-सीमा तय की जाती है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर बता देगा कि परियोजना कब पूरी होगी.

ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टक हब बनेगा मप्र

उन्होंने कहा कि मप्र टाइगर स्टेट है. टाइगर स्टेट का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने टाइगर कॉरिडोर के मंजूरी दी है, ये कॉरिडोर प्रदेश के चार प्रमुख नेशनल पार्क को जोड़ेगा. मंत्री ने दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि मप्र अब केवल सड़कों का जाल नहीं बिछाएगा, बल्कि देश का सबसे आधुनिक लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब बनकर भी उभरेगा.

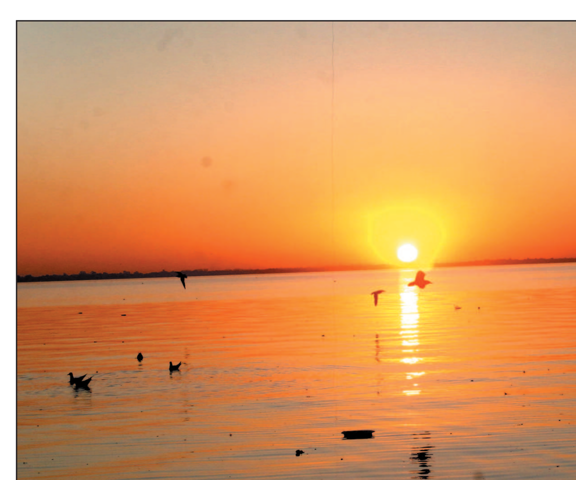

मध्यप्रदेश में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ा

भोपाल, 18 दिसंबर. मध्यप्रदेश में ठंड और घने कोहरे ने एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. गुरुवार को प्रदेश के 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल सहित 5 जिलों में शीतलहर का प्रभाव बना रहने की चेतावनी दी गई है.

कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार 19 दिसंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड में और इजाफा होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया कि ग्वालियर-चंबल और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की आशंका है. ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सीधी जिलों में घना से मध्यम कोहरा छा सकता है.

कई इलाकों में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक सिमटने की संभावना जताई गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. वहीं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर और इंदौर जिलों में शीतलहर का असर बना रहेगा.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. सागर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा, जबकि शेष संभागों में यह सामान्य के आसपास दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान भोपाल संभाग में सामान्य से 3.7 डिग्री तक कम रहा. इंदौर और उज्जैन संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 से 2.9 डिग्री कम रहा, जबकि शहडोल संभाग में यह सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया.

सीबीआई कार्रवाई | पूछताछ में खुल सकता है रिश्वतखोरों का बड़ा नेटवर्क

सीजीएसटी अधिकारी 22 तक सीबीआई की रिमांड पर

जबलपुर, 18 दिसंबर. ग्वारीघाट स्थित सीजीएसटी कार्यालय में सीबीआई जबलपुर ने चार लाख की रिश्वत लेते दो सीजीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद गुरुवार दोपहर न्यायालय लेकर पहुंचीऔर न्यायालय से आरोपियों की रिमांड की डिमांड की गई।

इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 22 दिसम्बर तक सीबीआई की रिमांड पर सौंप दिया। अब दोनों से सीबीआई सघन पूछताछ कर रही है। मामले में बड़ा नेटवर्क खुल सकता है। सूत्र बताते है कि

रिश्वतखोर अधिकारियों ने सूची बनाई हुई थी। इसके जरिए वे पहले जांच करते थे और फिर रिकवरी, टैक्स पर कारवाई का डर दिखाकर रिश्वत लेते थे। मामले की विस्तृत जांच जारी है। जिसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक विवेक त्रिपाठी ने सीबीआई जबलपुर में शिकायत कर बताया कि वे सतपुरा इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर के निदेशक हैं और जबलपुर में उनके चार होटल हैं। वर्ष 2018-19 में उनके एक होटल, सुकून सिटी व्यू का ओयो कंपनी के साथ संबद्धता थी। ओयो कंपनी से संबंधित जीएसटी का मामला जबलपुर के सीजीएसटी कार्यालय में लंबित है और इस संबंध में उनके होटल को करों के बकाया के लिए एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।

सीजीएसटी विभाग ने उनसे उनके होटल, सुकून सिटी व्यू जबलपुर के दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा था और उन्होंने नोटिस के लिखित उत्तर के माध्यम से सुकून सिटी व्यू के सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट के साथ सीजीएसटी विभाग को पहले ही जमा कर दिए हैं। हालांकि, जबलपुर के सीजीएसटी इंस्पेक्टर सचिन खरे ने होटल के खिलाफ मामला बंद करने और अपने पक्ष में आदेश देने के बदले में 4,00,000 रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से अपना काम करवाने का आश्वासन भी दिया।

रिश्वत की मांग के सत्यापन के दौरान, शिकायतकर्ता ने जबलपुर स्थित सीजीएसटी कार्यालय में निरीक्षक सचिन खरे और अधीक्षक बर्मन से बातचीत की। सीए हर्षित खंडेलवाल भी लंबित कार्यों और लोक सेवकों द्वारा रिश्वत की मांग के संबंध में हुई चर्चा में शामिल हुए। इसके बाद आगे की सत्यापन कार्यवाही की गई। जिसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और सीजीएसटी कार्यालय में दबिश दी जहां से रिश्वत लेते रंगे हाथों सचिन खरे, निरीक्षक, उप, सहायक आयुक्त विवेक वर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60